Ajay Kumar *v.* Chandigarh Administration and others
(S. S. Sandhawalia, C.J.)

एस.एस. संधावालिया, सी.जे. और एस.एस. सोढ़ी, जे. के समक्ष

अजय कुमार,-याचिकाकर्ता।

बनाम

चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य,-प्रतिवादी।

1982 की सिविल रिट याचिका संख्या 3750।

14 सितंबर 1982.

भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 14 और 15 - उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिए राज्य के स्वामित्व वाले संस्थानों में प्रवेश - प्रवेश के लिए एकमात्र मानदंड के रूप में योग्यता निर्धारित करने वाला प्रॉस्पेक्टस - उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की गई - प्रवेश के अंतिम दिन तक कुछ सीटें रिक्त रह जाना- ऐसी रिक्तियां प्रवेश की अंतिम तिथि पर कॉलेज परिसर में उपस्थित अभ्यर्थियों में से 'स्पॉट सेलेक्शन' द्वारा भरी जाती हैं- प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को प्रवेश की पेशकश नहीं की गई - ऐसा स्थान चयन - चाहे अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन हो - कॉलेज के कर्मचारियों के बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण - ऐसा आरक्षण - चाहे अमान्य और अनुच्छेद 14 के विरुद्ध अपमानजनक हो।

अभिनिर्णीत किया *कि राज्य की कार्रवाई को समानता के नियम की कसौटी पर परखा जाना चाहिए जो संविधान द्वारा राज्य को दिया गया है। मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 15 और 16 के समान पहलुओं के साथ निहित समानता खंड अब उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिए बासी संचालित संस्थानों में उम्मीदवारों के चयन में इतनी गहराई से प्रवेश कर गए हैं कि इसे लॉन्च करना बेकार होगा। पहले सिद्धांतों पर एक शोध प्रबंध पर। यह अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होता है कि उच्च शिक्षा के ऐसे संस्थानों में प्रवेश में अवसर की समानता अब उपरोक्त अनुच्छेदों के तहत नागरिक छात्रों के लिए एक गारंटीशुदा अधिकार है। संक्षेप में, यह उन लोगों की योग्यता पर विचार करने का अधिकार प्रदान करता है जो पात्रता की निर्धारित परीक्षा को पूरा करते हैं और उसके बाद योग्यता के अनुसार चयन करते हैं। इस संदर्भ में योग्यता का मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर किया जा रहा है, जो उद्देश्यपूर्ण भी है और संबंधित व्यक्ति को अच्छी तरह से ज्ञात भी है, अब तक इसे या तो प्रवेश के नियमों, प्रासंगिक प्रॉस्पेक्टस में शामिल किया गया है या अन्यथा जानकारी के लिए उपलब्ध कराया गया है। मुख्य बात यह है कि योग्यता पर यह विचार आम तौर पर निर्दिष्ट परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के पैमाने से मापा जाता है। यहां न्यायिक रूप से विकसित कानून का नियम*

भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि राज्य अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करते हुए भी मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता है। राज्य होने के नाते यह निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य है, जो इसके विपरीत किसी भी बाध्यकारी नियम के अभाव में इस संदर्भ में केवल योग्यता के आधार पर स्पष्टता को दर्शाता है। निष्पक्षता से कार्य करने का यह सिद्धांत समानता के मौलिक अधिकार और भेदभाव के खिलाफ निषेध के लिए बुनियादी है। उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिए राज्य संचालित संस्थानों में योग्यता के आधार पर चयन का सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हो गया है। इसके ठीक विपरीत यह मामला इस तथ्य पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करता है कि भेदभाव और मनमानी की दोहरी बुराई 'स्पॉट सेलेक्शन' के रूप में लेबल की गई चीज़ में अंतर्निहित है। अनिवार्य रूप से यह स्थान, समय और चयन के तौर-तरीके, यदि कोई हो, को निर्धारित करने के लिए मौके पर मौजूद व्यक्ति को पूरी तरह से निरंकुश शक्ति प्रदान करेगा। इसमें चयन करने में चयन प्राधिकारी का अनिर्देशित विवेक शामिल होता है। समान रूप से, यह उन व्यक्तियों के अधिकार का उल्लंघन करता है जो चयन के लिए पात्रता की कसौटी पर खरे उतरते हैं और समान मानदंड के साथ ई को मापने के संवैधानिक आदेश का उल्लंघन करते हैं। इस तरह की प्रक्रिया पहले से अनिर्दिष्ट स्थान पर और पहले से अनिश्चित समय पर होने की मात्र आकस्मिक परिस्थितियों पर संतुलन को झुका सकती है। निश्चित रूप से ऐसी विधि (यदि इसे इतना ऊंचा नाम दिया जा सकता है) संविधान में दिए गए समानता नियम और आधिकारिक न्यायिक मिसाल द्वारा विस्तृत और प्रतिपादित समानता नियम से बहुत दूर है। अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकार में निहित समानता के सिद्धांत और मनमानी कार्रवाई के खिलाफ न्यायिक रोक को तथाकथित 'स्पॉट सेलेक्शन' की आड़ में तात्कालिक सनक द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिए राज्य के स्वामित्व वाले संस्थानों में प्रवेश के संदर्भ में समानता नियम आकर्षित होता है, बाध्यकारी मंजूरी के बिना किसी भी अनुभवजन्य 'स्पॉट चयन' में अंतर्निहित है असमानता, मनमानी और भेदभाव के बीज और इसलिए, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। (पैरा 10, 11, 13 और 16)।

अशोक कुमार पानी बनाम राज्य एवं अन्य, ए.आई.आर. 1963 उड़ीसा 173.

प्रसन्न दिनकर सोहले आदि बनाम द द्योगिकी संस्थान, नागपुर और प्रभारी निदेशक लक्ष्मीनारायण अन्य, ए.आई.आर. 1982 बम्बई 176.

इससे असहमत:

अभिनिर्णीत किया *है कि एक उचित वर्गीकरण करने के लिए 6 विशेष विशेषताएं होनी चाहिए जो उस वर्ग को बाकियों से अलग करती हैं। वर्तमान मामले में इंजीनियरिंग कॉलेज के कर्मचारियों के बच्चों को वर्गीकृत करते समय ऐसा कोई समझदार अंतर वास्तव में, आरक्षण को किसी वैधानिक प्रावधान या किसी आधिकारिक निर्देश द्वारा दूर-दूर तक पवित्र किया गया नहीं दिखाया गया है। ऐसे में इस आरक्षण को भी रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता। (पैरा 25).*

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि माननीय न्यायालय इस पर कृपा करें: -

(i) उत्तरदाताओं से रिकॉर्ड की मांग करें और उसी मुद्दे के अवलोकन के बाद विशेष रूप से परमादेश की प्रकृति में एक उचित रिट, आदेश या निर्देश दें, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता को बी.एससी. में प्रवेश देने का आदेश दिया जाए। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और यदि आवश्यकता हो तो याचिकाकर्ता की योग्यता से नीचे के उम्मीदवारों का प्रवेश रद्द कर दिया जाए;

(ii) निषेधाज्ञा की प्रकृति में रिट जारी कर प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया जाए कि वह इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में याचिकाकर्ता की योग्यता से नीचे के किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश न दे;

(iii) इस रिट याचिका का निर्णय होने तक याचिकाकर्ता को अनंतिम रूप से स्वीकार करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, ताकि याचिकाकर्ता विभिन्न विषयों के अध्ययन में पिछड़ न जाए;

(iv) याचिकाकर्ता को याचिका की लागत का पुरस्कार देना;

(v) कोई अन्य राहत प्रदान करें, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों के तहत उचित समझे;

(iv)) ऐसे नियमों और शर्तों पर अनुबंध पी-1 से पी-3 की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दें, जिन्हें यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।

(vii) संशोधित उच्च न्यायालय नियमों और आदेशों के तहत आवश्यकतानुसार प्रतिवादियों को अग्रिम नोटिस जारी करने से छूट।

याचिकाकर्ता के वकील अश्वनी कुमार चोपड़ा।

प्रतिवादी 1 और 2 के लिए एस. बराड़, वकील, बी. बी. अग्रवाल और कंवलजीत सिंह।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद स्वरूप, संजीव पब्बी।

निर्णय

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.

1. उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिए राज्य के स्वामित्व वाले संस्थानों में प्रवेश के लिए जिसे शिष्टतापूर्वक "स्पॉट चयन" कहा जाता है, उसकी वैधता सोलह संबंधित रिट याचिकाओं के इस सेट में रीढ़ की हड्डी का मुद्दा बन गई है।

2. यहां उठने वाले मुद्दों को अजय कुमार बनाम चंडीगढ़ प्रशासन आदि, 1982 के सी.डब्ल्यू.पी नंबर 3750 में दिए गए कथनों से उपयुक्त रूप से चुना जा सकता है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तरी क्षेत्र में इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करने वाला एक प्रतिष्ठित संस्थान है। . यह सात इंजीनियरिंग विषयों में अध्ययन के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह पूरी तरह से राज्य के स्वामित्व और राज्य द्वारा प्रबंधित है। 1982-83 के शैक्षणिक सत्र के लिए, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज प्रॉस्पेक्टस (सत्र 1982-83) द्वारा प्रवेश के लिए 275 सीटों की पेशकश की गई थी, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज प्रॉस्पेक्टस (सत्र 1982-83) द्वारा प्रवेश के लिए 275 सीटों की पेशकश की गई थी, जिन्हें निम्नानुसार आवंटित किया गया था: -

"(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	*....65*
(ii) प्री-इंजीनियरिंग। उम्मीदवार (सामान्य पूल)	*.... 79*
(iii) बी.एससी. उम्मीदवार (सामान्य पूल)	*....9*
(iv) बी.एससी. केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कॉलेजों/	
संस्थानों से अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार।	*....13*
(v) प्री-इंजीनियरिंग/बी.एससी. भाग- I के अभ्यर्थी	
यू.टी., चंडीगढ़ में स्थित संस्थानों/कॉलेजों	
से उत्तीर्ण हुए हैं।	*....119*
	275"

जिसमें उपरोक्त के अलावा, 27 विदेशी पात्र उम्मीदवारों को भारत सरकार के

नामांकित व्यक्ति के रूप में प्रवेश दिया जाना था।

3. याचिकाकर्ता अजय कुमार ने अधिकतम 650 में से 436 अंक हासिल करके अपनी प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की और चार वैकल्पिक विषयों अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के अंकों के आधार पर मेरिट सूची के लिए उनके अंकों का प्रतिशत भी हासिल किया। , 68.67 प्रतिशत पर काम किया। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 'द ट्रिब्यून' दिनांक 3 जून 1982 (अनुलग्नक पी/2) में प्रकाशित एक नोटिस के जवाब में, याचिकाकर्ता ने निर्धारित फॉर्म पर प्रवेश के लिए विधिवत आवेदन किया। बाद में, 28 जून, 1982 को 'द ट्रिब्यून' में एक और नोटिस प्रकाशित किया गया (अनुलग्नक पी/3), जिसके अनुसार याचिकाकर्ता जिस श्रेणी में आता है, उसके उम्मीदवार, और 68 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को 2 जुलाई 1982 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। माना जाता है कि यह साक्षात्कार केवल मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन के उद्देश्य से था और उम्मीदवारों को योग्यता के अनुसार ही प्रवेश के लिए विचार किया जाना था। याचिकाकर्ता विधिवत उपस्थित हुआ और उस तारीख को मेरिट सूची तैयार की गई और उसके अनुसार, चंडीगढ़ प्री-इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए 119 सीटें और साथ ही जनरल पूल के प्री-इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए 79 सीटें विधिवत भरी गईं। प्रॉस्पेक्टस में दिए गए नुस्खे के अनुसार, चंडीगढ़ प्री-इंजीनियरिंग श्रेणी के लिए 41 की प्रतीक्षा सूची और जनरल पूल के प्री-इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए 59 की प्रतीक्षा सूची तैयार की गई थी। याचिकाकर्ता का नाम प्रतीक्षा सूची में रखा गया था और उसे आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में कोई अस्पष्ट रिक्ति होने पर, उसे शुल्क आदि जमा करने के लिए रिपोर्ट करने के लिए बुलाया जाएगा और प्रवेश दिया जाएगा। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह प्रतिवादी नंबर 2 से पूछताछ करता रहा, लेकिन उसे बताया गया कि कोई और सीट उपलब्ध नहीं है और उसके बाद 2 जुलाई, 1982 के बाद उसे कभी भी बुलाया या सूचित नहीं किया गया। नहीं है।

4. यह स्पष्ट रुख है कि प्रतिवादी नंबर 3, संजय कुमार गुप्ता, जिन्होंने 63.3 का बहुत कम प्रतिशत प्राप्त किया था, को बाद में कुछ अन्य लोगों के साथ प्रवेश दिया गया था, जिन्हें याचिकाकर्ता से भी कम अंक मिले थे। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, याचिकाकर्ता अन्य उम्मीदवारों के विवरण प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि ये रिकॉर्ड का मामला था जिस तक उसकी पहुंच नहीं थी।

5. यह रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि योग्यता के अनुसार तैयार की गई प्रतीक्षा सूची को समाप्त किए बिना प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा किसी भी अन्य उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। प्रतिवादी क्रमांक 3 एवं अन्य अभ्यर्थियों का प्रवेश इस शासनादेश का उल्लंघन है। इसलिए, इसे अवैध, मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया गया और इस प्रकार यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14

द्वारा प्रभावित हुआ।

6. पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल-प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर रिटर्न में, व्यापक तथ्यात्मक स्थिति विवादित नहीं है और रिट याचिका के पैराग्राफ 1 से 5 को स्वीकार कर लिया गया है। हालाँकि, यह विस्तार से बताया गया है कि 2 जुलाई, 1982 के बाद, चंडीगढ़ प्री-इंजीनियरिंग सीटों के संबंध में पाँच रिक्तियाँ निकलीं और 28 जुलाई 1982 को इन सीटों को भरने के लिए योग्यता के क्रम में 14 उम्मीदवारों को 30 जुलाई 1982 को सुबह 10 बजे रिपोर्ट करने के लिए तार भेजे गए थे। निम्नलिखित शब्दों में:-

"अपने आवेदन का संदर्भ लें बी.एससी. इंजीनियरिंग प्रवेश. (जे मेटलर्जी/एयरो में कुछ सीटें उपलब्ध हैं।) 30 जुलाई को सुबह 10 बजे शुल्क के साथ साक्षात्कार के लिए रिपोर्ट करें। 29 जुलाई से पहले टेलीग्राफ़िक रूप से उत्तर दें।"

इसी प्रकार, जनरल पूल में सीटों के संबंध में चार रिक्तियां निकलीं और प्रतीक्षा सूची में केवल 10 व्यक्तियों को समान पत्र और तार भेजे गए। उत्तरदाताओं का मानना है कि 2 अगस्त 1982 को, जिसे प्रवेश की अंतिम तिथि कहा जाता है, प्रतीक्षा सूची में से जिन अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था उनमें से केवल एक-एक अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए। इस प्रकार चंडीगढ़ प्री-इंजीनियरिंग कोटा में चार रिक्तियां और जनरल पूल प्री-इंजीनियरिंग कोटा में तीन रिक्तियां अभी भी खाली रह गईं और उसी तारीख को जनरल पूल के एक और उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। नतीजतन, शाम 4.30 बजे के बाद. 2 अगस्त, 1982 को, प्रवेश प्रभारी अधिकारी ने प्रिंसिपल को एक रिपोर्ट (अनुलग्नक आर/2) दी कि प्रवेश के लिए आठ सीटें उपलब्ध थीं और कुछ आवेदक जिन्हें पहले साक्षात्कार के लिए भी नहीं बुलाया गया था, वे प्रवेश की अपनी संभावनाओं के बारे में पूछताछ कर रहे थे और वे पहले से ही वहां मौजूद थे, और आग्रहपूर्वक अनुरोध कर रहे थे कि उन्हें प्रवेश दिया जाए। इस रिपोर्ट के आधार पर, प्रिंसिपल ने बाद में एक आदेश पारित किया, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

(i) प्री-इंजीनियरिंग, चंडीगढ़ की 4 रिक्तियों के विरुद्ध, उपस्थित सभी चंडीगढ़ प्री-इंजीनियरिंग आवेदकों के छात्रों के रोल कॉल लिए जा सकते हैं और उनकी पारस्परिक योग्यता के आधार पर प्रवेश की पेशकश की जा सकती है। यदि फिर भी चंडीगढ़ की कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें उनकी अंतर-योग्यता के आधार पर सामान्य पूल के आवेदकों को प्रदान किया जाएगा।

(ii) सामान्य पूल के उम्मीदवारों की 4 रिक्तियों के विरुद्ध, इन्हें उनकी अंतर-योग्यता के आधार पर उपस्थित सामान्य पूल प्री-इंजीनियरिंग उम्मीदवारों को पेश किया जाएगा। यदि इस श्रेणी की कुछ सीटें अभी भी खाली रहती हैं तो चंडीगढ़ प्री-

इंजीनियरिंग आवेदकों को उनकी अंतर-योग्यता के आधार पर यह पेशकश की जाएगी।

हालाँकि, ऊपर दी गई सलाह के अनुसार कार्रवाई करने से पहले कॉलेज परिसर में मौजूद सभी आवेदकों से संपर्क करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी आवेदक जो उपस्थित है और योग्यता में उच्चतर है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

मामला यह भी है कि इस आदेश के अनुसरण में, बाद में, 2 अगस्त, 1982 के उसी दिन, यह पाया गया कि चंडीगढ़ प्री-इंजीनियरिंग श्रेणी के केवल सात उम्मीदवार शाम 5.15 बजे उपस्थित थे। जिसमें प्रतिवादी नंबर 3 संजय कुमार गुप्ता भी शामिल हैं, जिन्हें तुरंत प्रवेश दे दिया गया। सामान्य पूल की श्रेणी में, केवल एक उम्मीदवार, मनोज गुप्ता उपस्थित थे, जिन्हें समान रूप से प्रवेश दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि बाद में, श्री अशोक कुमार, जिन्होंने एक सिविल मुकदमा दायर किया था, ने चंडीगढ़ प्रशासन को एक अभ्यावेदन दिया और उनके निर्देशों के तहत, उन्हें 10 अगस्त, 1982 को कॉलेज में अनंतिम प्रवेश दिया गया। विशेष रूप से याचिकाकर्ता के संबंध में प्रतिवादी की दलील इस प्रकार है: -

"यदि याचिकाकर्ता ऊपर बताए अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार 2 अगस्त, 1982 को उपस्थित था, संबंधित विषयों में उनकी उच्च योग्यता के आधार पर निश्चित रूप से प्रतिवादी नंबर 3 की प्राथमिकता में प्रवेश के लिए उस पर विचार किया गया होगा। उपरोक्त आधार पर, उत्तरदाताओं की ओर से यह दावा किया गया है कि 2 अगस्त, 1982 को स्वीकारोक्ति निष्पक्ष और तर्कसंगत आधार पर की गई है और किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है।

7. याचिकाकर्ता की ओर से, 'इंजीनियरिंग कॉलेज के रिकॉर्ड से एक विस्तृत प्रतिकृति संलग्नक पी/5 से पी/7 के साथ संलग्न करते हुए दायर की गई है। मामले के अंत में, प्रतिवादियों की ओर से इस प्रतिकृति का उत्तर भी रिकॉर्ड पर रखा गया था। दलीलों के इस हिस्से में किसी भी विवरण का विज्ञापन करना अनावश्यक है क्योंकि इसमें याचिकाकर्ता की ओर से ऐसे संकेत उठाए गए हैं जिन्हें उत्तरदाताओं की ओर से अस्वीकार कर दिया गया है। इसलिए, हम इस ठोस नियम के मद्देनजर इन कथनों के विवादास्पद हिस्से को नजरअंदाज करना पसंद करेंगे कि रिट क्षेत्राधिकार उलझे और विवादित तथ्यों के दलदल में प्रवेश करने के लिए उचित मंच नहीं है। इसे हाल ही में गुरु नानक विश्वविद्यालय बनाम डॉ. (श्रीमती) इकबाल कौर संधू और अन्य[1] मामले में पूर्ण पीठ द्वारा दोहराया गया है। यह देखने के लिए किसी महान विद्वता की आवश्यकता नहीं है कि यह क्षेत्राधिकार आम तौर पर

[1] AIR 1976 Pb. & Hy. 69

हलफनामों पर कथित और स्वीकार किए गए तथ्यों तक ही सीमित है या जिन्हें रिकॉर्ड पर गंभीरता से नहीं देखा गया है। जैसा कि सर्वविदित है, यह एक असाधारण उपाय है जिसका सहारा तब लिया जाता है जब बुनियादी तथ्यात्मक स्थिति विवाद में न हो। यह ध्यान में रखना होगा कि रिट क्षेत्राधिकार विवादास्पद मामलों के निर्धारण के लिए एक मुकदमे के माध्यम से नियमित परीक्षण का विकल्प नहीं है और न ही बनाया जा सकता है, जिसमें संबंधित पक्ष प्रासंगिक तथ्यों पर बिल्कुल विपरीत हैं। यह वास्तव में उन मामलों में विवेकाधीन रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार करने का एक कारण है जहां तथ्यों के जटिल और विवादित प्रश्न उठाए जाते हैं जब तक कि निश्चित रूप से एक बहुत ही असाधारण उपाय के रूप में रिट न्यायालय स्वयं साक्ष्य दर्ज करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है और फिर उस पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसलिए, हम कमोबेश स्वीकृत और स्थापित तथ्यों के आधार पर मामले पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे और बड़े सिद्धांत और स्थायी विचार-विमर्श के आधार पर इस मुद्दे पर निर्णय लेंगे।

8. दलीलों के उपरोक्त बायोडाटा से यह स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं के रुख का मूल यह है कि 2 अगस्त, 1982 को शाम 4.30 बजे के बाद, प्रतिवादी संख्या 12 के कार्यालय से एक प्रस्ताव आया कि परिणामी रिक्तियां यह उन अभ्यर्थियों में से भरा जाएगा जो आकस्मिक रूप से कॉलेज परिसर में उपस्थित थे और जिन्हें पहले साक्षात्कार के लिए भी नहीं बुलाया गया था। इस कमजोर आधार पर, प्रतिवादी-कॉलेज के प्रिंसिपल, जो मौके पर मौजूद थे, ने तदनुसार चयन करने के लिए 'स्पॉट-निर्णय' कहा जा सकता है। यहां उत्तरदाताओं का पूरा मामला यह है कि वह 'स्पॉट सेलेक्शन' का सहारा लेने का हकदार था और यह स्पष्ट रूप से अच्छे विश्वास में किया गया है, मामला अब चुनौती से परे है।

9. अब यह रुख एकदम से महत्वपूर्ण सवाल उठाता है - क्या उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य संस्थानों के संदर्भ में, 'स्पॉट-चयन' की अनुभवजन्य प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है?

10. यहां जो बात उजागर करने योग्य है वह यह है कि प्रतिवादी-इंजीनियरिंग कॉलेज एक राज्य के स्वामित्व वाला और राज्य द्वारा संचालित संस्थान है। इसलिए, यहां जो चुनौती दी जा रही है वह वस्तुत: राज्य की कार्रवाई है जिसे संविधान द्वारा राज्य को दिए गए समानता के नियम की कसौटी पर परखा जाना है। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 15 और 16 के अनुरूप पहलुओं के साथ निहित समानता खंड अब उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिए राज्य-संचालित संस्थानों में उम्मीदवारों के चयन में इतनी गहराई से प्रवेश कर गए हैं कि यह पहले सिद्धांत पर शोध प्रबंध शुरू करना काफी बेकार होगा। यह अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होता है कि उच्च शिक्षा के

ऐसे संस्थानों में प्रवेश में अवसर की समानता अब उपरोक्त अनुच्छेदों के तहत नागरिक-छात्रों के लिए एक गारंटीशुदा अधिकार है। संक्षेप में, यह उन लोगों की योग्यता पर विचार करने का अधिकार बताता है जो पात्रता की निर्धारित परीक्षा को पूरा करते हैं और उसके बाद योग्यता के अनुसार चयन करते हैं। इस संदर्भ में योग्यता का मूल्यांकन एक मानदंड के आधार पर किया जा रहा है, जो उद्देश्यपूर्ण भी है और संबंधित व्यक्तियों के लिए भी अच्छी तरह से जाना जाता है, जहां तक इसे प्रवेश के नियमों में शामिल किया गया है, प्रासंगिक प्रॉस्पेक्टस या अन्यथा जानकारी के लिए उपलब्ध कराया गया। मुख्य बात यह है कि योग्यता पर यह विचार आम तौर पर निर्दिष्ट परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के पैमाने से मापा जाता है।

11. यहां न्यायिक रूप से विकसित कानून का नियम भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि राज्य अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करते हुए भी मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता है। राज्य होने के नाते यह निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य है, जो इसके विपरीत किसी भी बाध्यकारी नियम के अभाव में इस संदर्भ में केवल योग्यता के आधार पर स्पष्टता को दर्शाता है। निष्पक्षता से कार्य करने (या इसे नकारात्मक रूप से कहें तो मनमानी से बचने) का यह सिद्धांत समानता के मौलिक अधिकार और भेदभाव के खिलाफ निषेध के लिए बुनियादी है।

12. हालाँकि यह मामला सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट प्रतीत होता है, यह अंतिम न्यायालय की मिसाल की एक लंबी श्रृंखला में काफी हद तक शामिल है। अधिकारियों को गुणा करना अनावश्यक है और डॉ. जगदीश सरन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य;[2] *मामले में इस मुद्दे को सीधे तौर पर कवर करने वाली कुछ हालिया मिसाल को निम्नलिखित शब्दों में उद्धृत करना पर्याप्त है -*

"यदि देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर की समानता संवैधानिक गारंटी है, तो एक उम्मीदवार जो दूसरे की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करता है वह प्रवेश के लिए प्राथमिकता का हकदार है। समान अंकों के लिए समान अवसर के इस नियम के अनुसार, सर्वोत्तम का चयन करते समय योग्यता ही कसौटी होनी चाहिए। जब हम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों जैसे शिक्षा के उच्च स्तर तक पहुँचते हैं तो यह प्रस्ताव अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आख़िरकार, चिकित्सा जैसे किसी भी महत्वपूर्ण क्षेत्र में शीर्ष तकनीकी विशेषज्ञता एक राष्ट्र की मानव संपत्ति है जिसके बिना इसकी प्रगति और विकास अवरुद्ध हो जाएगा। उच्च ग्रेड कौशल या विशेष प्रतिभा की भूमिका शिक्षा, नौकरियों और सामाजिक असंगतता के विषयों के निचले स्तर पर

[2] AIR 1980 S.C. 820

कम हो सकती है, लेकिन परिष्कृत कौशल और रणनीतिक रोजगार के उच्च स्तर पर अधिक हो सकती है। शिखर सम्मेलन में योग्यता का अवमूल्यन करना पेशेवर विशेषज्ञता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश के विकास के साथ अस्थायी होना है।

** **

** **

"ब्रास टैक की बात करें तो, समान अंकों से विचलन को केवल तभी मंजूरी दी जाएगी जब ऊपर निर्धारित आवश्यक शर्तें पूरी की जाती हैं"

** ** '

** **

"हम जानते हैं कि योग्यता को मापना कठिन है और अब जो तरीके प्रचलन में हैं, वे इतने अधिक वांछित हैं कि योग्यता के माप के रूप में अंकों की शपथ लेना घोर अंधविश्वास भी हो सकता है। लेकिन, निश्चित तकनीकों के अभाव में, हमें प्रवेश परीक्षाओं से ही निपटना होगा, और किसी भी दर पर, विकृति या तर्कहीनता के स्पष्ट मामलों को छोड़कर यह आमतौर पर अदालतों की सीमा से बाहर है।

13. उपरोक्त दृष्टिकोण को राज्य मध्य प्रदेश बनाम निवेदिता जैन,[3] *में दोहराया गया है। इस फैसले को पढ़ने से पता चलता है कि उनके आधिपत्य ने मध्य प्रदेश में राज्य मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के चयन के लिए योग्यता के नियम और उसके आवेदन की सावधानीपूर्वक जांच की। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिए राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में योग्यता के आधार पर चयन का सिद्धांत अब मिसाल कायम करके भी अच्छी तरह स्थापित हो गया है। इसके ठीक विपरीत यह मामला इस तथ्य पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करता है कि भेदभाव और मनमानी की दोहरी बुराई 'स्पॉट सेलेक्शन' के रूप में लेबल की गई चीज़ में अंतर्निहित है। अनिवार्य रूप से यह स्थान, समय और चयन के तौर-तरीकों, यदि कोई हो, को निर्धारित करने के लिए मौके पर मौजूद व्यक्ति को पूरी तरह से निरंकुश शक्ति प्रदान करेगा। इसमें चयन करने में चयनकर्ता प्राधिकारी का अनिर्देशित विवेक शामिल होता है। समान रूप से यह उन व्यक्तियों के अधिकार का उल्लंघन करता है जो चयन के लिए पात्रता की कसौटी पर खरे उतरते हैं और समान मानदंडों के साथ बराबरी को मापने के संवैधानिक आदेश का उल्लंघन करते हैं। जैसा कि वर्तमान मामले में स्पष्ट है, ऐसी प्रक्रिया पहले से अनिर्दिष्ट स्थान पर और पहले से अनिर्दिष्ट समय पर घटित होने की मात्र आकस्मिक परिस्थितियों पर संतुलन को झुका सकती है। निश्चित रूप से ऐसी विधि (यदि इसे इतना ऊंचा नाम*

[3] AIR 1981 S.C. 2045

दिया जा सकता है) संविधान में दिए गए और आधिकारिक न्यायिक मिसाल द्वारा विस्तृत और प्रतिपादित समानता नियम से बहुत दूर है। मुझे ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में निहित समानता के सिद्धांत और मनमानी कार्रवाई के खिलाफ न्यायिक रोक को तथाकथित 'स्पॉट सेलेक्शन' की आड़ में तात्कालिक सनक द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

14. 'स्पॉट चयन' की कथित वैधता को प्रमाणित करने के लिए उत्तरदाताओं की ओर से मूल निर्भरता अशोक कुमार पानी बनाम राज्य और अन्य पर है[4]। निस्संदेह यह मामला उत्तरदाताओं के रुख को समझने में मदद करेगा। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि निरीक्षण के बाद से पुलों से काफी पानी बह चुका है। फैसले पर गौर करने से पता चलता है कि यह पूरी तरह से दोहरे आधार पर आगे बढ़ता है कि छात्रों को किसी भी राज्य मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने का कोई अधिकार नहीं था और यह पूरी तरह से संबंधित अधिकारियों के विवेक का मामला था। इस आधार पर यह माना गया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विभिन्न कॉलेजों के संबंधित प्राचार्यों के विवेक को चुनौती नहीं दी जा सकती। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त निर्णय का आधार अब अंतिम न्यायालय के बाद के उदाहरणों द्वारा समाप्त हो गया है, जैसा कि पहले ही ऊपर उद्धृत किया जा चुका है, डॉ. जगदीश सरन और निवेदिता जैन के मामलों (सुप्रा) में, सबसे बड़े सम्मान के साथ मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक कुमार पाम के मामले (सुप्रा) में अनुपात कायम नहीं रह सकता है और यह अब अच्छा कानून नहीं है। अनिवार्य रूप से मुझे उस पर असहमति दर्ज करनी होगी।

15. ऊपर जो कहा गया है वह रामचन्द्र विष्णु बनाम मध्य प्रदेश राज्य के पहले के निर्णयों पर समान रूप से लागू होता है, न कि अधिक बल से।[5] और गोकुल प्रसाद बनाम एम.एम. सोहनी पेट्रोल,[6] जिन पर अशोक कुमार पाणि के मामले (सुप्रा) में भरोसा किया गया था। इन प्राधिकारियों का विचार यह था कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में वैधानिक बल नहीं था और इसलिए, सर्टिओरीरी और परमादेश का रिट इस संदर्भ में जगह से बाहर था। स्पष्टतः यह दृष्टिकोण अब संभवतः क्षेत्र पर पकड़ नहीं बना सकता है। इस संदर्भ में प्रसन्ना दिनकर सोहाल्क आदि बनाम प्रभारी निदेशक लक्ष्मीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर और अन्य,[7] मामले में डिवीजन बेंच के फैसले का भी संदर्भ दिया

[4] AIR 1963 Orissa 173.
[5] AIR 1961 M.P. 247.
[6] AIR 1962 M.P. 126.
[7] AIR 1982 Bom 176,

जाना चाहिए। उक्त मामले में भले ही लक्ष्मीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के लिए स्पॉट चयन को प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण रद्द कर दिया गया था, तथापि, एक गुप्त अवलोकन किया गया था कि 'स्पॉट एडमिशन' में कोई अवैधता नहीं होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऐसी प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता का दूर-दूर तक प्रचार नहीं किया गया था। चूँकि स्थान चयन को अन्यथा अवैध ठहराया गया था, विद्वान न्यायाधीशों का ध्यान स्पष्ट रूप से इसकी आंतरिक प्रकृति की ओर आकर्षित नहीं हुआ था। इस बिंदु पर सिद्धांत और नजीर की तनिक भी चर्चा नहीं होती। यदि प्रसन्ना के मामले को इस प्रस्ताव के लिए कोई वारंट माना जाता है कि वर्तमान संदर्भ में "स्पॉट चयन" संवैधानिक है तो पहले दर्ज किए गए कारणों से मैं सम्मानपूर्वक इससे असहमत होऊंगा।

16. इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिए राज्य के स्वामित्व वाले संस्थानों में प्रवेश के संदर्भ में समानता नियम आकर्षित होता है, कोई भी अनुभवजन्य बाध्यकारी मंजूरी के बिना 'स्पॉट चयन' (यह संभव हो सकता है इसमें भी संदेह है) इसमें असमानता, मनमानी और भेदभाव के बीज निहित हैं, और इसलिए, अनुच्छेद का उल्लंघन है

17. अब सामान्य से विशेष तक आगे बढ़ते हुए यह समान रूप से स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में कथित 'स्पॉट चयन' पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज प्रॉस्पेक्टस (सत्र 1982-83) में निहित प्रवेश के नियमों के साथ लंबे समय से संघर्ष में है। उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं बाध्यकारी माना जाता है। यह चयन के बुनियादी नियमों और समान रूप से इस चयन के बाद उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्तियों को भरने के लिए प्रदान करता है। उक्त प्रॉस्पेक्टस के पृष्ठ 23 पर योग्यता के नियम को स्पष्ट शब्दों में निम्नानुसार वर्णित किया गया है: -

"(iii) विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों का प्रवेश संबंधित योग्यता सूची के आधार पर किया जाता है"। प्रक्रियात्मक पहलू को पृष्ठ 27 पर पैरा 5 में निम्नानुसार विस्तृत किया गया है: -

"5. प्रवेश के लिए पात्र उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के अनुसार पत्र या प्रेस अधिसूचना के माध्यम से साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और उन्हें कुछ विशेष तिथियों पर चयन समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। उन्हें अपने साथ विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र - मैट्रिकुलेशन/हायर सेकेंडरी, प्री¬इंजीनियरिंग, बी.एससी. लाना होगा। और अन्य प्रमाणपत्र जिनकी प्रतियाँ मूल रूप में आवेदन आदि के साथ संलग्न की गई हैं।"

इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि समानता की संवैधानिक गारंटी और मनमानी के खिलाफ न्यायिक रोक के अलावा, विशेष नियम स्वयं योग्यता के आधार पर चयन निर्दिष्ट करते हैं। यह स्वीकृत स्थिति है कि इसे चार वैकल्पिक विषयों- अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के अंकों के आधार पर निर्धारित किया जाना था और इस बिंदु पर कोई तथ्यात्मक विवाद नहीं है।

18. न केवल मूल चयन के चरण में बल्कि बाद की रिक्तियों के बाद के चरण में भी योग्यता के नियम और प्रक्रिया पृष्ठ 27 नोट (ii) पर अच्छी तरह से निर्धारित हैं। इसे निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है: -

"नोट (ii) उन उम्मीदवारों के मामले में जो नियत तिथि पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित नहीं होते हैं या साक्षात्कार के तुरंत बाद कॉलेज का बकाया जमा नहीं करते हैं, उनकी उम्मीदवारी स्वचालित रूप से रद्द कर दी जाएगी और रिक्तियां हो सकती हैं। योग्यता के क्रम में अगले उम्मीदवारों को पेश किया जाता है। इस संबंध में किसी भी पत्राचार या अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।" और फिर से पृष्ठ 23 पर निम्नानुसार: -

(11) प्रवेश के समय शाखा का आवंटन उस समय विशेष शाखा में उपलब्ध सीटों और उम्मीदवारों द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित किसी विशेष शाखा के लिए वरीयता क्रम के आधार पर किया जाएगा। हालाँकि, यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि से पहले कुछ छात्रों के कॉलेज छोड़ने के कारण सीटें खाली हो जाती हैं, तो प्रवेशित छात्रों को आवेदन पत्र में उल्लिखित वरीयता क्रम के अनुसार ऊपर की ओर स्थानांतरित कर दिया जाएगा और शाखा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को छोड़ना/स्थानांतरित करना। विभिन्न शाखाओं की परिणामी रिक्तियों को योग्यता और किसी विशेष शाखा में उपलब्ध सीटों के अनुसार प्रतीक्षा सूची में से चुने गए नए उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

19. इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि चयन के बाद उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के संबंध में भी, जिनसे हम मुख्य रूप से चिंतित हैं, प्रवेश नियम विशिष्ट और श्रेणीबद्ध हैं। परिणामी रिक्तियों को प्रॉस्पेक्टस में दी गई प्रतीक्षा सूची में से भरना होगा और इन्हें भरने के लिए भी योग्यता के नियम को सर्वोपरि बनाया गया है। इसलिए, आवश्यक निहितार्थ से, प्रॉस्पेक्टस में शामिल बाध्यकारी नियम इसके जनादेश के विपरीत किसी भी चयन पर रोक लगाते हैं।

20. अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस विवादित 'स्पॉट चयन' का सहारा लिया गया है, वह प्रॉस्पेक्टस में ऊपर दिए गए प्रत्येक आदेश का उल्लंघन है। ऐसा लगता है कि योग्यता के नियम और सभी योग्य उम्मीदवारों पर विचार को स्पष्ट

रूप से नजरअंदाज कर दिया गया है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि वर्तमान मामले में न केवल प्रतीक्षा सूची विधिवत तैयार की गई थी, बल्कि 41 उम्मीदवारों को चंडीगढ़ प्री-इंजीनियरिंग कोर्स की श्रेणी में और 59 उम्मीदवारों को सामान्य पूल के प्री-इंजीनियरिंग उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा गया था। यह स्वयं उत्तरदाताओं का मामला है कि प्रतीक्षा सूची के इन सभी उम्मीदवारों को परिणामी रिक्तियों के बारे में सूचित करने का प्रयास भी नहीं किया गया। इन सूचियों के समाप्त होने की बात तो दूर, यह स्वीकृत स्थिति है कि बाद में उनमें से केवल कुछ को ही प्रवेश की पेशकश की गई। इसके बजाय चयन की पूरी तरह से कालानुक्रमिक प्रक्रिया

2 अगस्त, 1982 को शाम 5.15 बजे कॉलेज परिसर में छात्रों की आकस्मिक उपस्थिति के बीच से प्रतीक्षा सूची में से मुश्किल से एक या दो छात्रों को जगह मिली और वह भी उनके योग्यता क्रम में नहीं थे। यह स्पष्ट रूप से इस प्रकार है कि यहां स्पॉट चयन स्पष्ट रूप से प्रॉस्पेक्टस में शामिल प्रवेश के स्वीकार्य रूप से बाध्यकारी नियमों का उल्लंघन है और इस स्कोर पर भी इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

21. एक पल के लिए (बिना स्वीकार किए) यह मान लें कि किसी दूरस्थ आपात स्थिति में, किसी स्थान का चयन शायद स्वीकार्य हो सकता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में प्रक्रिया की कमज़ोरियाँ और अनियमितताएँ समान रूप से इसे ख़राब करती हैं। प्रसन्ना दिनकर सोहले के मामले (सुप्रा) में इस पहलू को अच्छी तरह से विस्तृत किया गया है और उसी आधार पर दोबारा जाना बेकार है। हम इस दृष्टिकोण से सम्मानजनक सहमत हैं कि स्पॉट चयन की वैधता की धारणा पर भी यह प्रक्रिया की अनियमितताओं से दूषित हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप छात्र उम्मीदवारों के बीच भेदभाव होगा। वर्तमान मामले में, जो चीज़ प्रमुखता से ध्यान खींचती है वह प्रकाशन की पूर्ण कमी का तथ्य है, सबसे पहले, इस निर्णय के संबंध में भी कि स्पॉट चयन किया जाएगा और दूसरे, उस स्थान और समय के बारे में जहां यह किया जाएगा। प्रतिवादी के स्वयं के रुख से और अनुबंध आर 2 में आंतरिक साक्ष्य से, यह स्पष्ट है कि 2 अगस्त 1982 को शाम 4.30 बजे के बाद पहली बार स्थान चयन के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था। परिशिष्ट आर. 2 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

"उपरोक्त तालिका से ऐसा प्रतीत होता है कि आज शाम 4.30 बजे, 2 अगस्त, 1982, जो प्रवेश की अंतिम तिथि है, कॉलेज में अभी भी सामान्य पूल में चार सीटें और चंडीगढ़ के छात्रों के कोटे में चार सीटें उपलब्ध हैं जिन्हें पेश किया जा सकता है। उम्मीदवार।"

प्रभारी अधिकारी प्रवेश का नोट इस प्रकार शाम 4.30 बजे के बाद ही तैयार कर

लिया गया और फिर प्रिंसिपल को भेज दिया गया, जिन्होंने बाद में इस पर विचार किया और शाम 5.15 बजे तक स्पॉट चयन करने का आदेश दर्ज किया, उसी तिथि पर चयन करने की बात कही गई है। 8 अभ्यर्थियों को महाविद्यालय परिसर में उपस्थित पाकर तत्काल पूर्ण कर लिया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रवेश के प्रभारी अधिकारी और प्रधानाचार्य के अलावा किसी को भी इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि किसी भी स्थान का चयन किया जाना था और यदि हां, तो कहाँ और कब। वास्तव में श्री अग्निहोत्री उत्तरदाताओं के लिए बहुत

अजय कुमार बनाम चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य

(एस.एस. संधावालिया, सी.जे.)

काफी हद तक स्वीकार किया कि यहां कुछ नहीं था। उसके लिए जो भी प्रकाशन हो। ऐसा होने पर यह स्पष्ट है कि प्रतीक्षा सूची के सभी पात्र छात्रों को इच्छित स्थान चयन या शाम 5.15 बजे उपस्थित होने की आवश्यकता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 2 अगस्त, 1982 को कॉलेज परिसर में। दलजीत सिंह मिन्हास और अन्य, बनाम पंजाब राज्य और अन्य[8],) में पूर्ण पीठ ने अनुच्छेद 16 के संदर्भ में, इस प्रकार अभिनिर्णीत किया*: -*

"उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, किसी को सावधानी बरतनी चाहिए कि यह नहीं समझा जाना चाहिए कि सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्तियाँ गुप्त तरीके से की जानी हैं। जो स्पष्ट रूप से निहित है वह यह है कि भरे जाने वाले पदों के लिए बड़े पैमाने पर जनता या उस वर्ग या स्रोत तक जिसके लिए भर्ती सीमित हो सकती है, पर्याप्त प्रचार देने का तरीका और तरीका आवश्यक रूप से विवेकपूर्ण विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। संबंधित प्राधिकारी. संभवतः, अधिकांश मामलों में सार्वजनिक विज्ञापन अभी भी संबंधित उम्मीदवार तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक कार्यालय में चयन और नियुक्तियों के संदर्भ में जो कहा गया है वह मुझे उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिए राज्य के स्वामित्व वाले संस्थानों में सीटों के चयन के संबंध में अनुच्छेद 14 पर समान रूप से लागू होता है।

22.) फिर भी यह स्वीकृत स्थिति है कि चंडीगढ़ प्री-इंजीनियरिंग श्रेणी के लिए प्रतीक्षा सूची में 41 उम्मीदवार और सामान्य पूल श्रेणी में 59 उम्मीदवार थे, फिर भी टेलीग्राम द्वारा सूचना क्रमशः केवल 14 उम्मीदवारों और 10 उम्मीदवारों को दी गई थी। . गौरतलब है कि टेलीग्राम केवल 28 जुलाई को भेजे गए थे, जिसमें उम्मीदवारों से 30 जुलाई को रिपोर्ट करने और 29 तारीख से पहले टेलीग्राफ़िक रूप

[8] AIR 1978 Pb. & Hy. 117.

से सूचित करने के लिए कहा गया था। संबंधित उम्मीदवारों द्वारा इन टेलीग्रामों की प्राप्ति या उनकी प्रतिक्रिया के बारे में भी उत्तरदाता चुप हैं। यह कि प्रतिक्रिया के लिए निर्दिष्ट समय बहुत कम था और उसके प्राप्त न होने की संभावनाएँ मौजूद हो सकती हैं, यह इस मामले में बहुत बड़ी बात है और इसमें विस्तार की आवश्यकता नहीं है। फिर इन टेलीग्रामों में 30 तारीख को किसी स्थान चयन की दूर-दूर तक बात नहीं की गई और न ही उत्तरदाताओं का मामला है कि इन सभी उम्मीदवारों को बाद में तीन दिन बाद, 2 अगस्त को एक विशेष समय पर उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया था। यह सामान्य मामला है कि प्रॉस्पेक्टस के आदेश के अनुसार तैयार की गई प्रतीक्षा योग्यता सूची के सभी उम्मीदवारों को सूचित करने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया। प्रकाशन की अनुपस्थिति इस तथ्य से और अधिक स्पष्ट होती है कि शाम 5.15 बजे भौतिक समय पर केवल 8 छात्र उपस्थित थे, जबकि यह सामान्य मामला है कि उनमें से सैकड़ों ने इंजीनियरिंग अनुशासन के लिए आवेदन किया था और सीटों की कमी और 2 जुलाई, 1982 को मूल रूप से चयनित लोगों की तुलना में योग्यता में नीचे होने के कारण निराश थे। यह उत्तरदाताओं का मामला है कि उपरोक्त तिथि पर चयन पूरा होने के बाद परिणामी रिक्तियां उत्पन्न होने लगीं और इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि इसके बाद दो से तीन सप्ताह से अधिक समय तक अलग-अलग श्रेणियों में प्रतीक्षा सूची से इन्हें विधिवत क्यों नहीं भरा गया। समग्र मूल्यांकन से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तात्कालिकता की कथित स्थिति प्रतिवादी की स्वयं की रचना थी। ऐसी स्थिति में भी, यह जरूरी है कि प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन को नियंत्रित करने वाले नियमों और सिद्धांतों का ध्यान रखा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टीबीटीई सीटों के वर्तमान मामले में कथित तौर पर उत्पन्न होने वाली असामान्य स्थिति में भी योग्यता के मानदंड से विचलन न हो। प्रवेश की अंतिम तिथि समाप्त होने पर रिक्त छोड़ दिया जाना।

23. समान रूप से, यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी नंबर 3, जिसे कई याचिकाकर्ताओं की तुलना में योग्यता में काफी नीचे प्रवेश दिया गया है। न ही इसमें कोई संदेह है कि इसी तरह स्वीकार किए गए कुछ अन्य उम्मीदवार भी कई याचिकाकर्ताओं की तुलना में योग्यता में कम हैं। वास्तव में इस संदर्भ में उत्तरदाताओं ने अजय कुमार के मामले में दावा करते हुए वस्तुत: यह दावा स्वीकार कर लिया है कि यदि याचिकाकर्ता 2 अगस्त, 1982 को उपस्थित होता, तो निश्चित रूप से उसके आधार पर प्रतिवादी नंबर 3 की वरीयता में प्रवेश के लिए उस पर विचार किया जाता। उच्च योग्यता. इस प्रकार यह माना जाता है कि 2 अगस्त को शाम 5.15 बजे कॉलेज परिसर से उनकी अनुपस्थिति की आकस्मिक परिस्थिति के लिए, कुछ याचिकाकर्ताओं के पास उस समय प्रवेश पाने वालों की तुलना में प्रवेश का स्पष्ट अधिकार है।

24. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि यहां अपनाई गई प्रक्रिया भी ऐसी अनियमितताओं और अवैधताओं से भरी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप स्पष्ट भेदभाव होता है और परिणामस्वरूप 2 अगस्त, 1982 को और उसके बाद चयन प्रभावित होता है।

25. एक अतिरिक्त मुद्दा जो समान रूप से सराहनीय है, फिर से सीडब्ल्यूपी 3669/1982 संजय गुलाटी बनाम में स्पष्ट नोटिस की मांग करता है।

चंडीगढ़ प्रशासन. और अन्य. इसमें पैरा क्रमांक 15 में निम्नलिखित कहा गया है:-

"याचिकाकर्ता की योग्यता के क्रम में नीचे के उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों और आई के गलत इरादे से अंतिम क्षण में समायोजित किया गया है।"

अनुचित लाभ और प्राथमिकता देने तथा अनावश्यक प्रतिफल के लिए। इतना ही नहीं प्रॉस्पेक्टस में इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षण स्टाफ के उम्मीदवारों/बेटों और बेटियों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी, बल्कि उन्होंने प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित श्रेणियों के अलावा लगभग 5/6 उम्मीदवारों को भी प्रवेश दिया है। इन सभी अभ्यर्थियों का प्रवेश रद्द किया जा सकता है। इस पर उत्तरदाताओं का उत्तर इस प्रकार है:-

"इस पैरा में लगाए गए आरोपों को गलत बताया गया है। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, दाखिले उचित, न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से किए गए हैं।

पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ के कर्मचारियों के सात बच्चों को 2 अगस्त, 1982 को उनकी इंटर-से-मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया गया है। चूंकि ये सीटें चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सत्र 1982-83 के लिए प्रॉस्पेक्टस के प्रावधानों, यानी 275 के अलावा बनाई गई थीं, इन दाखिलों से किसी भी तरह से याचिकाकर्ता के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।"

उपरोक्त से यह स्वीकृत स्थिति है कि 2 अगस्त, 1982 के बाद, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के कर्मचारियों के बच्चों की कथित क्लॉइस्टेड श्रेणी से सात सीटें भरी गई हैं। माना जाता है कि ऐसा कोई आरक्षण न तो किसी वैधानिक प्रावधान में मौजूद है और न ही प्रॉस्पेक्टस में सीटों के वर्गीकरण में मौजूद है। उत्तरदाता पहले इस आरक्षण को करने और फिर 2 अगस्त, 1982 को सीटें भरने के अधिकार के स्रोत के बारे में गुप्त रूप से चुप हैं। हमारा विचार है कि प्रसन्ना दिनकर सोहले के उपरोक्त मामले के फैसले में यह मुद्दा इतनी अच्छी तरह से

कवर किया गया है कि इस मामले को विस्तार से बताना अनावश्यक है। उसमें, विश्वविद्यालय कर्मचारियों के वार्डों के पक्ष में सीटों के समान आरक्षण को चुनौती दी गई थी। यह वास्तव में इसे नागपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 की धारा 11(4) के तहत कुलपति की मंजूरी भी प्राप्त थी और कथित तौर पर इसकी धारा 4 और 75 के तहत कवर किया गया था। फिर भी इस आरक्षण को डिवीजन बेंच ने सिद्धांत और अंतिम न्यायालय के उदाहरणों पर निम्नलिखित शब्दों में विस्तृत चर्चा के बाद रद्द कर दिया: -

"एक और महत्वपूर्ण कारक पर विचार किया जाना चाहिए। वर्गीकरण करते समय कुछ ऐसी विशिष्टताएँ अवश्य होनी चाहिए जो उस वर्ग को बाकियों से अलग करती हों। उदाहरण के लिए, राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अलग-अलग वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि वे स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी हैं। विदेशी मिशन में कार्यरत कर्मचारी एक अलग वर्ग होंगे क्योंकि ऐसे कर्मचारियों को अपने बच्चों की शिक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार, राजनीतिक पीड़ितों के बच्चे एक अलग वर्ग होंगे क्योंकि ऐसे वार्डों को उनके माता-पिता की गतिविधियों (स्वतंत्रता संग्राम में) के कारण सामान्य शैक्षणिक सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो दूसरों को मिलेंगी। वर्तमान मामले में, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को अलग से वर्गीकृत करते समय ऐसा कोई समझदार अंतर नहीं है। ऐसे कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किये जाने की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को वे लोग नहीं कहा जा सकता जो किसी अन्य कारण से अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सके

• अजीब, कठिनाइयाँ। इस प्रकार 'विश्वविद्यालय कर्मचारियों के वार्ड' किसी भी अन्य कर्मचारियों के वार्डों के बराबर हैं। इतना ही नहीं बल्कि वे अन्य व्यक्तियों जैसे छोटे व्यापारियों, व्यापारियों, कारीगरों आदि के वार्डों के बराबर भी हैं। इस चर्चा के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वार्डों के पक्ष में चार आरक्षण बनाकर, विश्वविद्यालय ने भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया है और समानता के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है। भेदभाव को इस तथ्य से देखा जा सकता है कि इस श्रेणी के चार छात्रों (जो रिट याचिका संख्या 2707/1979 में उत्तरदाता संख्या 3, 6, 7 और 8 हैं) को प्रवेश दिया गया था, हालांकि योग्यता के आधार पर उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा सकता था। (प्रतिवादी संख्या 8 को छोड़कर) अंकों का प्रतिशत हमारे सामने कई याचिकाकर्ताओं की तुलना में बहुत कम था।

और

** * * इस तरह से याचिकाकर्ताओं को यह कहने का अधिकार है कि प्रश्न में आरक्षण खराब है। इसलिए, परिणाम यह है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के*

बच्चों के पक्ष में चार आरक्षणों को कायम रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

उपरोक्त टिप्पणियों के प्रकाश में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता बच्चों के पक्ष में आरक्षण पर हमला करने में और भी मजबूत स्थिति में हैं। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ के कर्मचारी और उनमें हुए प्रवेश। इसमें उक्त आरक्षण को किसी भी वैधानिक प्रावधान या किसी आधिकारिक निर्देश द्वारा दूर-दूर तक पवित्र नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस आरक्षण को रद्द करने और इसके परिणामस्वरूप सीटों को भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

26. प्रतिनिधि ने अपने सभी बचावों को गुण-दोष के आधार पर निरस्त कर दिया, पिछली बार निजी प्रतिवादी नंबर 3 की ओर से प्रक्रियात्मक तकनीकीताओं पर मामले को रोकने का प्रयास किया गया था। यह तर्क दिया गया कि प्रत्येक उम्मीदवार जिसे विवादित चयन में या बाद में प्रवेश दिया गया है, उसे विशेष रूप से एक पार्टी के रूप में शामिल नहीं किया गया है और इसलिए, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है। जैसा कि पहले की कुछ विस्तृत चर्चा से स्पष्ट है, यहां चुनौती स्थान चयन की अवधारणा और अपनाई गई प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद 14 के उल्लंघन को लेकर है। यह उत्तरदाताओं के व्यक्तिगत मामले नहीं हैं जिन्हें मुद्दे में डाला जा रहा है बल्कि राज्य की कार्रवाई की संवैधानिकता को मुद्दा बनाया जा रहा है। फिर से, याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रतिवादी-कोलपे के रिकॉर्ड तक किसी भी पहुंच के अभाव में, वे ऐसे प्रत्येक उम्मीदवार का पता लगाने और निर्दिष्ट करने में असमर्थ थे जिन्हें असंवैधानिक रूप से प्रवेश दिया गया था, सिवाय उन लोगों को छोड़कर जिन्हें इस तरह से फंसाया गया था। इस संदर्भ में यह अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होता है कि, निजी उत्तरदाता उचित पक्ष हो सकते हैं लेकिन आवश्यक पक्ष नहीं हैं जिनकी अनुपस्थिति राहत से इनकार करने का आधार हो सकती है। महाप्रबंधक, दक्षिण-मध्य रेलवे, सिकंदराबाद और अन्य बनाम ए.वी.आर. में सिद्धांती और अन्य, अपने कुछ कर्मचारियों की वरिष्ठता, वेतन आदि के निर्धारण से संबंधित रेलवे बोर्ड के नीतिगत निर्णयों को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई थी। इसी तरह की आपत्ति यह थी कि प्रतिकूल रूप से प्रभावित निजी व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया था जैसा कि उत्तरदाताओं ने उठाया था। इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए यह देखा गया-

" * * * वर्तमान मामले में, राहत का दावा केवल रेलवे के खिलाफ किया गया है जिसे उसके प्रतिनिधि के माध्यम से पक्षकार बनाया गया है। आक्षेपित निर्णयों के अनुसार, विशिष्ट व्यक्तियों की तुलना में याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता तय करने वाली किसी सूची या आदेश को चुनौती नहीं दी जा रही है। याचिकाकर्ता की*

वरिष्ठता के पुन: समायोजन के परिणामस्वरूप जिन कर्मचारियों के प्रभावित होने की संभावना थी

15 अक्टूबर 1952 के बोर्ड के निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, अधिक से अधिक, उचित पक्ष थे और आवश्यक पक्ष नहीं थे, और उनका गैर-जुड़ना रिट याचिका के लिए घातक नहीं हो सकता था।" इसी तरह की आपत्ति को फिर से रामचन्द्र शंकर देवधर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य [9] मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय के भीतर नरेश कुमार जोशी और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य[10] मामले में इस प्रकृति की एक तकनीकी आपत्ति को निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दिया गया था: -

" * *. हालाँकि, मुझे इन आपत्तियों में कोई योग्यता नहीं दिखती, सबसे पहले, इस कारण से कि याचिकाकर्ता किसी विशेष उम्मीदवार के चयन को चुनौती नहीं दे रहे हैं; वे जिस चीज को चुनौती दे रहे हैं वह उम्मीदवारों के चयन का तरीका और तरीका है और दूसरी बात, दलीलों से यह स्पष्ट है कि विशेष जिले के उम्मीदवारों का चयन करते समय चयनित उम्मीदवारों की योग्यता पर विचार नहीं किया गया था। अन्य जिले. इस स्वीकृत स्थिति के सामने चयन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानने के लिए किसी और सामग्री की आवश्यकता नहीं है।*

उपरोक्त आधिकारिक व्याख्या के बाद निजी उत्तरदाताओं को पक्षकार बनाने के संबंध में उठाई गई आपत्ति को आवश्यक रूप से खारिज कर दिया जाना चाहिए।

27. विशेष रूप से अशोक कौशिक के मामले 2 के विज्ञापन में कहा गया है कि उन्हें प्रतिवादी संख्या 1. चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश के तहत प्रवेश दिया गया है, यह ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने केवल सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था। . उसे प्रवेश देने के लिए सिविल कोर्ट द्वारा कोई अंतरिम राहत या निर्देश नहीं दिया गया था। फिर भी चंडीगढ़ प्रशासन उसके प्रवेश का निर्देश दिया। इसलिए, यह आदेश योग्यता नियमों और प्रॉस्पेक्टस में निर्धारित बाध्यकारी शर्तों के उल्लंघन के दोष से समान रूप से ग्रस्त है और इसलिए, इसे कायम रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

28. स्पष्टता के लिए, यह याद दिलाया जाता है कि इस रिट याचिका में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के नामांकन पर विदेशी विद्वानों को दिए गए प्रवेश को

[9] (1974) 1 S.L.R. 470.
[10] 1982 (1) S.L.R. 15.

कोई चुनौती नहीं है और यह किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

29. उपरोक्त पैरा 16, 20, 24 और 25 में आए निष्कर्षों के आलोक में अंतिम निष्कर्ष निकालते हुए और उसके आवश्यक परिणाम के रूप में, निम्नलिखित उम्मीदवारों को दिए गए प्रवेश रद्द कर दिए जाते हैं;

(i) जिन्हें पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के कर्मचारियों के बेटों और बेटियों के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश दिया गया;

(ii) जिन्हें 2 अगस्त 1982 को 'स्पॉट सेलेक्शन' के आधार पर भर्ती किया गया; और

(iii) इसके बाद जिन लोगों को प्रॉस्पेक्टस में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना प्रवेश दिया गया, उनमें अशोक कौशिक भी शामिल हैं, जिन्हें कथित तौर पर 10 अगस्त, 1982 को प्रवेश दिया गया था।

तदनुसार प्रतिवादी नंबर 2, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल को परिणामी रिक्तियों को योग्यता के क्रम में प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों में से भरने के लिए एक और निर्देश जारी किया जाता है। आधिकारिक उत्तरदाता वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जो उनकी ओर से किसी भी गलती के कारण उत्पन्न नहीं हुई है, इस प्रकार चयनित उम्मीदवारों को अपने व्याख्यान पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

30. जहां तक उन अभ्यर्थियों का संबंध है जिनका इस आदेश के परिणामस्वरूप अपना प्रवेश खोने की संभावना है, अधिकारियों को पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में उनके प्रवेश के लिए उनके द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि वापस करने का निर्देश जारी किया जाता है।

31. सभी रिट याचिकाएं उपरोक्त शर्तों के साथ लागत सहित स्वीकार की जाती हैं। वकील की फीस रु. प्रत्येक मामले में 500.

एन.के.एस.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्ण वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा मेंइसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णयर्ण का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुकत रहेगा ।

Checked By:
Deepak yadav
Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy
Chandigarh